(a) whether it is a fact that many . Public Sector Undertakings (PSUs) hav$_e$ been referred to BIFR by Gov. ernment in the recent past;

(b) if so, what are the details thereof:

(c) the number of Public Sector Undertakings located in Madhya Pra desh which have been referred to BIFR with details thereof; and

(d) whether any final decision nave been taken with regard to the re. commendations of the BIFR?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY. OF INDUSTRY (SHRI P. K. TtHUNGON: (a) and (b) 54 sick industrial companies in the public sector as per 1990-91 performance are liable *to* be referred to the BIFR as per provisions of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act 1985.

(c) There is one undertaking (i.e. M/s. NTC (MP) Limited) with re gistered office in Madhya Pradesh which would come under the purview of BIFR. -

(d) Decisions can be taken only after the BIFR findings are available.

Industrial growth centres in Madhya Pradesh

2384. SHRI GHUFRAN AZAM:
SHRI SURESH PACHOURI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether it is a fact that in 1989 some Industrial growth centres were sanctioned by the central Government for Madhya Pradesh;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether all the growth centres sanctioned by Government have been established in Madhya Pradesh;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) by when all the growth centres are likely to be established in Ma dhya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRl P. J-KURIEN): (a) to (e) Under the new Growth Centre Scheme, Madhya Pradesh was allocated six growth centres. These are as under:—

S. No.	Name of the growth centre	District
1	Borai	Drug
2	Chainpura	. Guna
3	Ghirongi	. Bhind
4	Kheda	. Dhar
5	Sittara	Raipur
6.	Satlapur	Raisen

Out of these, the State Government submitted Project Reports for 5 growth centres viz. Kheda. Ghirongi, Chainpura, Borni and Siltara which have been approved. The State Gov, eminent are yet to send the project report for the growth centre to be set up in Satlapur. The Scheme is proposed to be implemented during the Eighth Five Year Plan period.

2385. *[Transferred- to the 2ilh March,* 1992].

आयशर ट्रेक्टर्स लिमिटेड, फरीदाबाद हरियाणा द्वारा विनिर्मित किये गये ट्रेक्टर

2386. श्रीमती सत्या बहिन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयशर सोना (352) ट्रेक्टरों का विनिर्माण आयशर ट्रेक्टर लिमिटेड, फरीदाबाद (हरियाणा) द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी को लाइसेंस कब जारी किया गया था तथा इसे कितने हार्स पावर का लाइसेंस दिया गया था;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त कम्पनी ने कितने ट्रैक्टर विनिर्मित किये;

(घ) क्या ये ट्रैक्टर सभी प्रकार की तकनीकी बारी-जांच और प्रायोगिक परीक्षण पूरे किये जाने के पश्चात् किसानों को सौंपे जाते हैं;

(ङ) कम्पनी को या तो किसानों से या फिर एजेंसियों से इन ट्रैक्टरों की गारन्टी की अवधि के दौरान तकनीकी खामियों या इंजन की खामियों के संबंध में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) कम्पनी ने इन तकनीकी खामियों को दूर करने के लिये क्या कार्रवाहियां की हैं तथा प्रभावित किसानों को प्रतिपूर्ति करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) से (च) मैं० आयशर टैक्ट्रस लिमिटेड के अनुसार, ट्रैक्टर माडल आयशर सोना (35 हार्स पावर) का निर्माण उनकी सहयोगी कंपनी मै. कैपोल फार्म इक्यूपमेंट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा वर्ष 1977 में मंजूर हुए अपने लाइसेंस के तहत किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे केवल 46 ट्रैक्टरों का निर्माण किया गया है। खरीददारों को सौंपे जाने से पहले इन सभी ट्रैक्टरों की जांच की जाती है।

(ङ) विनिर्माता के अनुसार केवल 3% मामलों में बड़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(च) उत्पाद में आधुनिकीकरण और सुधार निरंतर किए जाते हैं तथा इन ट्रैक्टरों की निर्माण संबंधी खराबियों के मामले में गारन्टी अवधि के बाद भी किसानों की शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है।

मारुति उद्योग लिमिटेड कर्मचारी संघ द्वारा गैर-सरकारीकरण का विरोध

2387. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारुति उद्योग लिमिटेड कर्मचारी संघ ने गैर-सरकारीकरण के प्रस्ताव का विरोध किया है और यदि हां, तो संघ की क्या-क्या मुख्य मांगें हैं; और

(ख) क्या कम्पनी के गैर-सरकारीकरण के बारे में निर्णय लेते समय सरकार ने वर्तमान कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तों और उनके भविष्य पर भी विचार किया है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Growth Centre at Karaikal

2388. SHRI V. NARYANASAMY-, Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have id. entifled Karaikal region to set up growth centre there; and

(b) if so, when the said growth centre is likely to be set up in Karaikal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN); (a) and (b) Under the Growth Centre Scheme, Union Territory of Pondicherry has been allotted one growth centre and Karaikal have been selected for its location. The Project will be implemented during the Eighth Five Year Plan period.

Rejection of Maruti Cars due *to* sub. standard tyres

2389. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government't attention has been drawn to a news item which appeared in the Times of In-